



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64951

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5929/2026

दिलशाद

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: अतुल कुमार कुशवाहा

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार कुशवाहा और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री ओ.पी. सिंह की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक दिलशाद की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे पुलिस स्टेशन लोहामंडी, जिला आगरा में दर्ज मामला अपराध संख्या 417/2025, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 8/20 के तहत, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत इरादे से झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, 125 ग्राम चरस, जो वाणिज्यिक मात्रा से बहुत कम है, आवेदक के संयुक्त कब्जे से बरामद होना बताया गया है। आवेदक, जो 25.8.2025 से जेल में है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक का एक मामले में आपराधिक इतिहास है।

5. एफआईआर के अनुसार, 125 ग्राम चरस, जो कि व्यावसायिक मात्रा से बहुत कम है, आवेदक के पास से मिली है। यह भी कहा गया है कि आवेदक के भागने या गवाहों को छेड़ने की कोई संभावना नहीं है। उसका आपराधिक इतिहास है, जिसे आवेदक के ज्ञापन में समझाया गया है। और आवेदक 25.8.2025 से जेल में है।

6. सभी तथ्यों, प्रकृति और दस्तावेजों से मिले सबूतों को देखते हुए और एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 37 को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, जमानत दी जा सकती है। इसलिए, यह जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. आवेदक-दिलशाद, जो उपरोक्त मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक तय तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा।

8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026

कुमार मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”